

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12253/2019

मेसर्स गोटेन लाइमस्टोन खनिज उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय डी7, शास्त्री नगर, जोधपुर राजस्थान में है, इसके पावर ऑफ अटॉर्नी धारक श्री राजेश केडिया पुत्र श्री बजरंग लाल केडिया, उम्र 55 वर्ष, निवासी 53 ऑफिसर्स फ्लैट, जुबली रोड, उत्तरी सहार, जमशेदपुर झारखंड के माध्यम से है।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. संयुक्त सचिव, खान (ग्रेड 2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. सहायक खान अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, गोटेन, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर।
5. जेके सीमेंट लिमिटेड, गांव गोटेन, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर राजस्थान।

---- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के लिए	: श्री कमलाकर शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अलंकृता शर्मा श्री मधुसूदन सिंह राजपुरोहित श्री अंजय कोठारी की सहायता से
राज्य के लिए	: श्री महावीर बिश्नोई, एएजी श्री गौरव बिश्नोई, एएजी
प्रतिवादीगण संख्या 5 के लिए(जे.के. सीमेंट लिमिटेड)	: श्री सुधीर गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमित मेहता द्वारा सहायता प्राप्त श्री हिमांशु सोनी

न्यायाधीश दिनेश मेहता

निर्णयआरक्षित दिनांक : 25.09.2024रिपोर्ट योग्यघोषित दिनांक : 05.11.2024न्यायालय द्वारा :

सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठसंख्या	पैरा संख्या
1.	प्रस्तावना	2 से 3	1 से 3
2.	तथ्यात्मक मैट्रिक्स	3 से 7	4.1 से 4.29
3.	याचिकाकर्ता का मामला	7 से 12	5 से 25
4.	राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ	13 से 15	26 से 35
5.	प्रतिवादीगण संख्या	15 से 18	36 से 47
6.	प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ	18 से 20	48 से 56
7.	चर्चा और निष्कर्ष	20 से 34	58 से 111

1. प्रचुर रिकॉर्ड के बीच, एक छोटा सा सवाल है।
2. विवाद की उत्पत्ति याचिकाकर्ता कंपनी के गठन में निहित है - एक साझेदारी फर्म से इसका रूपांतरण और फिर, इसके शेयरों को अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड (इसके बाद "यूटीसीएल" के रूप में संदर्भित) में स्थानांतरित करना। हालांकि इसे एक साधारण कॉर्पोरेट पुनर्गठन के रूप में चित्रित किया गया था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 20.01.2016 को सिविल अपील संख्या 434/2016 (इसके बाद "सर्वोच्च न्यायालय के फैसले" के रूप में संदर्भित) में दिए गए अपने फैसले द्वारा खनिज अधिकारों का गुप्त हस्तांतरण पाया गया।
3. अब जो सवाल सामने आया है, वह यह है कि क्या इन दोनों लेन-देन को राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम, 2017 (इसके बाद "2017 के नियम" के रूप में संदर्भित) द्वारा मान्य किया गया है और क्या खनिज अधिकारों को याचिकाकर्ता या उसके उत्तराधिकारी - अल्ट्रा टेक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज / रिकॉर्ड किया जा सकता है।
4. प्रासंगिक तथ्य, संक्षेप में, निम्नानुसार हैं:-

तथ्यात्मक मैट्रिक्स:

4.1 खनिज - चूना पत्थर के लिए 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाला एक खनन पट्टा (खनन पट्टा संख्या 45/93) मेसर्स गोटेन लाइमस्टोन खनिज उद्योग

(जिसे आगे "जीएलकेयू या फर्म" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) नामक एक साझेदारी फर्म को दिया गया था।

4.2 उक्त खनन पट्टे को समय-समय पर नवीनीकृत किया गया था और 04.04.2024 तक वैध रहना था।

4.3 वर्ष 2012 में, फर्म के तत्कालीन भागीदारों ने फर्म द्वारा चलाए जा रहे व्यवसाय को चलाने के लिए खुद को एक 'प्राइवेट लिमिटेड कंपनी' में बदलने का फैसला किया।

4.4 परिणामस्वरूप, 26.03.2012 को मेसर्स गोटन लाइमस्टोन खनिज उद्योग प्राइवेट लिमिटेड नामक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई (जिसे आगे "जीएलकेयूपीएल या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी" कहा जाएगा)।

4.5 कंपनी के निगमन के तुरंत बाद, फर्म ने राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम, 1986 (जिसे आगे "1986 के नियम" कहा जाएगा) के नियम 15 के तहत सहायक खनन अभियंता, गोटन के समक्ष दिनांक 28.03.2012 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें याचिकाकर्ता - नव निगमित कंपनी के पक्ष में खनिज अधिकार और खनन पट्टे को स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी गई।

4.6 उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत करते समय, फर्म ने दावा किया कि फर्म के सभी मौजूदा भागीदार नव निगमित कंपनी के निदेशक हैं और इसके द्वारा कोई विचार या प्रीमियम नहीं लिया गया है।

4.7 प्रतिवादीगण संख्या 4 ने सिफारिश की कि पट्टा विलेख प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर हस्तांतरित किया जाए।

4.8 इस प्रकार की गई सिफारिशों के आधार पर, निदेशक (खान) ने दिनांक 25.04.2012 के आदेश के अनुसार प्रीमियम राशि सहित लागू शुल्कों के भुगतान की शर्त पर याचिकाकर्ता - गोटन लाइमस्टोन खनिज उद्योग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को विषयगत खनन पट्टे के हस्तांतरण की अनुमति दी।

4.9 निदेशक (खान) द्वारा दी गई अनुमति के अनुसरण में, नियम 15(4) के तहत निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार, हस्तान्तरणकर्ता फर्म और हस्तान्तरित कंपनी के बीच दिनांक 08.08.2013 को एक हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया गया।

4.10 यद्यपि वर्तमान मामले के लिए इसका अधिक महत्व नहीं है, लेकिन एक सहायक तथ्य के रूप में, यह ध्यान में रखा जा सकता है कि साझेदारी फर्म ने 04.02.1997 को एक आवेदन दिनांक 31.01.1997 को प्रस्तुत किया था, और मेसर्स जेके व्हाइट सीमेंट

वर्क्स, गोटन-प्रतिवादीगण संख्या 5 को अपने 10 वर्ग किलोमीटर के पट्टा क्षेत्र में से 2.041738 वर्ग किलोमीटर (204.1738 हेक्टेयर) भूमि के हस्तांतरण की मांग की थी।

4.11 याचिकाकर्ता-कंपनी के इस अनुरोध को निदेशक (खान) ने दिनांक 11.08.1997 के अपने पत्र के माध्यम से यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि 1986 के नियम 15 के तहत खनन अधिकारों के आंशिक हस्तांतरण का कोई प्रावधान नहीं है।

4.12 प्रतिवादीगण संख्या 5 ने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे राज्य सरकार ने दिनांक 02.12.1997 के आदेश के माध्यम से अनुमति दे दी और मामले को निदेशक (खान) को इस निर्देश के साथ वापस भेज दिया कि वे आंशिक हस्तांतरण के लिए प्रस्ताव भेजें, साथ ही 1986 के नियम 65 के अनुसार छूट देने का प्रस्ताव भी भेजें।

4.13 रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, लगभग 14 वर्षों की अवधि के लिए राज्य सरकार के दिनांक 02.12.1997 के आदेश के अनुसरण में कोई आदेश पारित नहीं किया गया था और केवल 05.09.2012 को निदेशक (खान) ने दिनांक 1986 के उक्त आवेदन को खारिज कर दिया था। 04.02.1997 को आंशिक हस्तांतरण के लिए।

4.14 दिनांक 05.09.2012 को आदेश पारित करते समय, निदेशक (खान) ने राज्य सरकार के दिनांक 13.08.2012 के संचार का हवाला दिया और उस पर भरोसा किया, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि खनन अधिकारों के आंशिक हस्तांतरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है और साथ ही दिनांक 27.01.1999 के पहले के आदेश पर भी भरोसा किया।

4.15 प्रतिवादीगण संख्या 5 ने बदले में निदेशक (खान) के दिनांक 05.09.2012 के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 404/2013) पेश की, जिसके तहत साझेदारी फर्म (प्रतिवादीगण संख्या 5 - जेकेडब्ल्यूसी) द्वारा दायर 204.1738 हेक्टेयर क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया।

4.16 उक्त रिट याचिका, हालांकि सीधे तौर पर संबंधित नहीं थी, पर इस मामले की बहस पूरी होने के तुरंत बाद सुनवाई का प्रस्ताव था, जैसा कि सभी उपस्थित वकीलों ने सुझाव दिया था।

4.17 वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह ध्यान देने योग्य है कि 21.04.2014 को राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता कंपनी को एक नोटिस भेजा था जिसमें पूछा गया था कि 25.04.2012 के आदेश को क्यों न शून्य घोषित किया जाए जिसके तहत खनन पट्टा संख्या 45/93 के संबंध में पट्टा अधिकार (साझेदारी फर्म से

याचिकाकर्ता - निजी लिमिटेड कंपनी को) हस्तांतरित किए गए थे और खनन पट्टे का निर्धारण क्यों न किया जाए।

4.18 याचिकाकर्ता ने दिनांक 04.06.2014 को जवाब दाखिल किया तथा अपना बचाव प्रस्तुत किया, लेकिन राज्य सरकार के पक्ष में जवाब नहीं आया और दिनांक 16.12.2014 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत न केवल हस्तांतरण की अनुमति देने वाले दिनांक 25.04.2012 के आदेश को निरस्त कर दिया गया, बल्कि खनन पट्टा भी निर्धारित कर दिया गया।

4.19 दिनांक 16.12.2014 के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता-कंपनी ने एक रिट याचिका (एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 9669/2014) प्रस्तुत की थी, जिसे इस न्यायालय के समन्वय पीठ ने दिनांक 25.03.2015 के आदेश के तहत अनुमति दे दी थी।

4.20 राज्य तथा प्रतिवादीगण संख्या 5-जेकेडब्ल्यूसी द्वारा इसके विरुद्ध दायर अंतर-न्यायालय अपीलों को दिनांक 14.05.2015 के आदेश के तहत एक खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था।

4.21 राज्य तथा प्रतिवादीगण संख्या 5-जेकेडब्ल्यूसी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग विशेष अनुमति याचिकाएं प्रस्तुत कीं। राज्य की विशेष अनुमति याचिका को बाद में सिविल अपील संख्या 434/2016 में परिवर्तित कर दिया गया तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 20.01.2016 के अपने निर्णय के तहत इसे अनुमति दे दी।

4.22 अपील को स्वीकार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि साझेदारी फर्म (गोटन लाइमस्टोन खनिज उद्योग) से निजी लिमिटेड कंपनी (गोटन लाइमस्टोन खनिज उद्योग प्राइवेट लिमिटेड) का गठन और फिर उक्त निजी लिमिटेड कंपनी की संपूर्ण शेयर होल्डिंग्स को अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड को हस्तांतरित करने जैसे दोनों लेन-देन, यदि अलग-अलग देखे जाएं तो इनमें कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं है, लेकिन यदि लेन-देन को एक साथ देखा जाए तो यह खनन पट्टे के हस्तांतरण के लिए कानूनी आवश्यकता से बचने और लेन-देन में शामिल पक्षों को निजी लाभ पहुंचाने के लिए जनता की हानि के लिए एक उपकरण साबित होता है।

4.23 उपरोक्त निर्णय के बाद याचिकाकर्ता ने 10.05.2017 को राज्य सरकार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया और प्रार्थना की कि विषयगत खदान के हस्तांतरण की अनुमति दी जाए।

4.24 आवेदन प्रस्तुत करते समय, याचिकाकर्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय के पैरा संख्या 38 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि 2017 के नव प्रख्यापित नियमों के नियम 27 में याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा किए गए लेनदेन जैसे खनिज रियायत के हस्तांतरण की अनुमति दी गई है।

4.25 आवेदन में यह भी दावा किया गया था कि खनन पट्टे के हस्तांतरण के बाद, संपूर्ण खनिज का उपयोग उसकी होल्डिंग कंपनी यूटीसीएल के कैप्टिव उपयोग के लिए किया जाएगा और याचिकाकर्ता कंपनी अंततः यूटीसीएल में विलय कर लेगी।

4.26 याचिकाकर्ता कंपनी ने यह भी कहा कि वह निर्धारित प्रीमियम/हस्तांतरण शुल्क और अन्य शुल्क का भुगतान करेगी।

4.27 याचिकाकर्ता के उक्त आवेदन के बाद होल्डिंग कंपनी - यूटीसीएल द्वारा दो अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील की राय भी दी गई।

4.28 याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को राज्य सरकार ने अपने दिनांक 28.11.2017 के आदेश के तहत इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि 2017 के नियमों के नियम 27 के अनुसार, खनन पट्टे को पूर्व अनुमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है और किसी कंपनी में निदेशक(ओं) का परिवर्तन हस्तांतरण के बराबर है। राज्य के अनुसार, चूंकि कंपनी के निदेशक को बदलने से पहले कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए हस्तांतरण अवैध था।

4.29 राज्य सरकार ने आगे कहा कि विचाराधीन खनन पट्टे का निर्धारण किया जा चुका था और विचाराधीन क्षेत्र राज्य सरकार के कब्जे में था। राज्य के अनुसार, चूंकि अन्यथा समाप्त किए गए खनन पट्टे के हस्तांतरण का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए याचिकाकर्ता का आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य था।

याचिकाकर्ता का मामला:

5. उपरोक्त संदर्भित दिनांक 28.11.2017 के आदेश पर प्रश्न उठाते हुए याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है।

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कमलाकर शर्मा ने न्यायालय को तथ्यात्मक मैट्रिक्स के माध्यम से निर्देशित किया, जिसे पूर्ववर्ती पैराग्राफों में समाहित किया गया है, साथ ही प्रासंगिक प्रावधानों और दस्तावेजों के माध्यम से यह तर्क दिया कि विषयगत आदेश तथ्यों और कानून के विपरीत है।
7. यह तर्क दिया गया कि आदेश एक ओर तो असंबद्ध और तर्कहीन है और दूसरी ओर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। उन्होंने दिनांक 28.11.2017 के आक्षेपित आदेश को पूरी तरह से पढ़ा और तर्क दिया कि यदि राज्य सरकार की राय थी कि याचिकाकर्ता का दिनांक 10.05.2017 का आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य था, तो उसे याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए था।
8. उन्होंने यह कहते हुए आलोचना की कि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करने के लिए कोई कारण नहीं बताए हैं।
9. उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16.12.2014 के आदेश को बरकरार रखा था और इस न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया था, लेकिन इस तरह के निरस्तीकरण के बावजूद, राज्य सरकार को एक महीने की अवधि के भीतर विचाराधीन लेनदेन जैसे लेनदेन को कवर करने के लिए नीति बनाने और संबंधित खनन पट्टे के संबंध में निर्णय लेने के निर्देश जारी किए गए थे।
10. उन्होंने तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने का तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय चाहता था कि राज्य सरकार लेनदेन को नियमित करे। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक भाग को, विशेष रूप से, पैरा-38 को यह बताने के लिए पढ़ा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के भाग्य को पूरी तरह से सील नहीं किया है। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह तैयार की जाने वाली नीति के आलोक में पूरे मामले पर फिर से विचार करे।
11. यह तर्क दिया गया कि राज्य सरकार को याचिकाकर्ता के आवेदन पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिए और उसके खनन अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, खासकर तब जब विषयगत खनन पट्टे द्वारा कवर किए गए क्षेत्र पर कोई तीसरे पक्ष के अधिकार नहीं बनाए जा सकते, लेकिन राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया है।

12. यह तर्क देते हुए कि आदेश अस्पष्ट और गूढ़ है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। और इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने न्यायालय को नियम 2017 के नियम 27 के माध्यम से ले गए और प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकार ने नीति बनाई है और नियम 27 में उप-नियम (7), (8) और (9) के रूप में नए प्रावधान पेश किए हैं, जो नियम अन्यथा 1986 के नियम 15 के समरूप हैं।

13. दोनों प्रावधानों की तुलना करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियम 2017 के नियम 27 के उप-नियम (7) से (10) को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को प्रभावी करने के लिए पेश किया गया है और इसलिए, नए पेश किए गए प्रावधानों का लाभ याचिकाकर्ता-कंपनी को दिया जाना चाहिए था, जिसके मामले में नीति बनाने के निर्देश दिए गए थे।

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नियम 2017 के नियम 27 के उपनियम (7) का खंड (i) स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के मामले को कवर करता है और जब उसने लागू शुल्क का भुगतान करने के लिए स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की थी, तो राज्य सरकार के पास याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने का कोई उचित कारण नहीं था।

15. उन्होंने तर्क दिया कि नियम 2017 के नियम 27 के उप-नियम (7), (8) और (11) नियम 27 के उप-नियम (1) से (6) से पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र हैं और उप-नियम (7) के खंड (i) से (v) में उल्लिखित माने गए हस्तांतरण या आकस्मिकताओं के मामले में पूर्व-अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

16. इस संबंध में, उन्होंने जोर देकर कहा कि उप-नियम (8) में प्रयुक्त भाषा यह स्पष्ट करती है कि माने गए हस्तांतरण की स्थिति में, पट्टेदार या लाइसेंसधारी को केवल उप-नियम (9) के अनुसार आवेदन शुल्क और प्रीमियम राशि के साथ 60 दिनों के भीतर किसी भी बदलाव के बारे में खनन अभियंता या सहायक खनन अभियंता को सूचित करना आवश्यक है।

17. दूसरे शब्दों में, उनकी दलील यह है कि नियम 27 के उप-नियम (1) में दी गई लिखित में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व सहमति की आवश्यकता को उप-नियम (7) के विभिन्न खंडों में उल्लिखित या माने गए हस्तांतरण के मामलों के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है।

18. यह तर्क दिया गया कि यदि उप-नियम (7) के अंतर्गत आने वाले लेन-देन के लिए पूर्व सहमति लेने का कोई इरादा था, तो ऐसी आवश्यकता को निर्दिष्ट न करने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रावधान "पट्टेदार या लाइसेंसधारी को 60 दिनों की अवधि के भीतर किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करना होगा" यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि ऐसे मामलों में पूर्व अनुमति समाप्त कर दी गई है।

19. यह तर्क दिया गया कि उप-नियम (1) के तहत परिकल्पित 'पूर्व सहमति' और उप-नियम (8) के तहत परिवर्तन के बारे में 60 दिनों में दी जाने वाली सूचना एक-दूसरे के विपरीत हैं और इसलिए, राज्य का यह रुख कि चूंकि कोई पूर्व सहमति नहीं ली गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता का आवेदन खारिज किए जाने योग्य था, कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है।

20. नियम 27 के उपनियम (11) के प्रावधान, विशेषकर इसके परंतुक की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि नीलामी के अलावा अन्य हस्तांतरण के मामले में एक वर्ष की लॉक-इन अवधि निर्धारित की गई है, लेकिन उपनियम (7) के खंड (i) से (v) के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में कोई लॉक-इन अवधि प्रदान नहीं की गई है। इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि नियम 27 द्वारा "खनिज रियायत का हस्तांतरण" शीर्षक के अंतर्गत दो अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। पहला नियमित हस्तांतरण और दूसरा उपनियम (7) के अंतर्गत आने वाले माने गए हस्तांतरण या मामले। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उपनियम (7) द्वारा शासित मामले उपनियम (1) में दिए गए हस्तांतरण के मामलों से पूरी तरह अलग हैं।

21. उन्होंने तर्क दिया कि उप-नियम (1) की प्रारंभिक अभिव्यक्ति कि पट्टेदार या लाइसेंसधारी सक्षम प्राधिकारी की लिखित में पूर्व सहमति के बिना खनन अधिकारों को हस्तांतरित या सौंप नहीं सकता है, नियम 27 के उप-नियम (7) द्वारा कवर किए गए परिवर्तनों पर लागू नहीं होता है।

22. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने नियम 28 में निहित प्रावधान, विशेष रूप से उप-नियम (1) के खंड (xix) का भी उल्लेख किया और प्रस्तुत किया कि ये शर्तें नियम 27 के उप-नियम (7) के खंड (i) से (v) द्वारा शासित मामलों को कवर करने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि खंड (xix) का प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि निर्दिष्ट समय

में उपर्युक्त परिवर्तनों को सूचित करने में विफलता हस्तांतरण के अधिकार के लिए घातक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे अधिकतम दो लाख रुपये के अधीन प्रति दिन पांच सौ रुपये की दर से विलंब शुल्क का भुगतान करके प्रस्तुत किया जा सकता है। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि राज्य सरकार अधिक से अधिक विलम्ब शुल्क वसूल सकती है जो अधिकतम दो लाख रुपये हो सकता है, श्री शर्मा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के आवेदन को सीधे खारिज करने वाला निर्णय अवैध है और 2017 के नियम 27 और 28 के प्रावधानों के विपरीत है।

23. उपरोक्त दलीलों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता-कंपनी ने राज्य सरकार को अपने पत्र दिनांक 09.08.2012 (अनुबंध-25 के साथ प्रत्युत्तर) के माध्यम से हुए लेन-देन के बारे में सूचित किया था। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि सूचना दी जा चुकी थी, इसलिए नियम 27 के प्रावधानों के आलोक में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार न करने का राज्य का निर्णय रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के अनुरूप नहीं है।

24. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस तथ्य से परिचित है कि साझेदारी फर्म द्वारा, जब वह एक निजी लिमिटेड कंपनी में तब्दील हुई थी, पूर्व सहमति प्राप्त की गई थी और स्वतंत्र रूप से विचार किए जाने के बावजूद, दोनों लेन-देन अर्थात् साझेदारी फर्म को निजी लिमिटेड कंपनी में बदलना और यूटीसीएल द्वारा निजी लिमिटेड कंपनी के शेयरों की खरीद में कुछ भी गलत या अवैध नहीं था, इसने राज्य को नीति बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एक बार नीति तैयार हो जाने और उप-नियम (7) के तहत मान लेने की व्यवस्था कर दिए जाने के बाद, जिसमें याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह शामिल है, राज्य सरकार तकनीकी आधार पर आवेदन को खारिज नहीं कर सकती, जबकि मूल रूप से लेन-देन में कोई अवैधता नहीं है।

25. उन्होंने बारी-बारी से तर्क दिया कि चूंकि चूना पत्थर को एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक प्रमुख खनिज घोषित किया गया है, इसलिए इसे पट्टा अधिकार हस्तांतरित करने या एमएमडीआर अधिनियम की धारा 12(ए)(6) के तहत इसके आवेदन पर विचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

राज्य की दलीलें:

26. श्री महावीर बिश्रोई, विद्वान अपर महाधिवक्ता ने 2017 के नियमों के नियम 1(3) को पढ़कर अपना मामला शुरू किया और इस बात पर जोर दिया कि 2017 के नियम 01.03.2017 से लागू हो गए हैं और तर्क दिया कि नियम लागू होने से पहले जो लेन-देन पूरे हो चुके थे, वे नियमों के दायरे में नहीं आ सकते।

27. उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि विषयगत खनन पट्टा संख्या 45/93 का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा 16.12.2014 को किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निस्संदेह इस न्यायालय की एकल पीठ ने अपने दिनांक 25.03.2015 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था और उक्त आदेश को रद्द कर दिया था और खंडपीठ ने दिनांक 14.05.2015 के अपने निर्णय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण को बरकरार रखा था, लेकिन अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.01.2016 के निर्णय के आधार पर, पट्टा विलेख को समाप्त करने वाला दिनांक 16.12.2014 का उक्त आदेश पुनर्जीवित हो गया।

28. उन्होंने प्रस्तुत किया कि 10.05.2017 को, जब आवेदन प्रस्तुत किया गया था, याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई खनन पट्टा अस्तित्व में नहीं था और, इसलिए, याचिकाकर्ता के पास यूटीसीएल को पट्टा अधिकारों के हस्तांतरण का दावा करने या आवेदन करने का कोई मौजूदा अधिकार नहीं था।

29. श्री बिश्रोई ने न्यायालय को विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से अवगत कराते हुए बताया कि निजी लिमिटेड कंपनी के निगमित होने के पश्चात (26.03.2012 को) पट्टेदार ने 28.03.2012 को साझेदारी फर्म के साझेदारों के हस्ताक्षरों के तहत हस्तांतरण हेतु पूर्व सहमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया तथा परिणामी पट्टा विलेख दिनांक 08.05.2013 को निष्पादित करते समय फर्म ने स्पष्ट वचन दिया था कि उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई समझौता नहीं किया है तथा इसके खनन अधिकार किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं, जबकि याचिकाकर्ता की अपने खनन अधिकार यूटीसीएल को हस्तांतरित करने की मंशा स्पष्ट थी।

30. उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता को खनन पट्टा हस्तांतरित किए जाने के तुरंत बाद, निजी लिमिटेड कंपनी की संपूर्ण शेयरधारिता 23.07.2012 को यूटीसीएल को हस्तांतरित कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि 06.08.2012 को इसके चार में से तीन निर्देश बदल दिए गए तथा याचिकाकर्ता कंपनी यूटीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली

सहायक कंपनी बन गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि लेन-देन की यह श्रृंखला यूटीसीएल को अवैध रूप से खनन अधिकार हस्तांतरित करने के लिए एक उपकरण के अलावा कुछ नहीं थी।

31. उन्होंने जोर देकर कहा कि 16.12.2014 को पट्टे की समाप्ति पर पट्टे वाले क्षेत्र का कब्जा तुरंत ले लिया गया था और उसके बाद से कब्जा हमेशा राज्य के पास रहा। फिर उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप खनन पट्टा समाप्त हो गया था, इसलिए न तो खनन पट्टे को याचिकाकर्ता के नाम पर पुनर्जीवित किया जा सकता है और न ही इसे प्रार्थना के अनुसार हस्तांतरित किया जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई जीवित अधिकार नहीं है।

32. श्री बिश्रोई ने तर्क दिया कि 2017 के नियमों के प्रावधानों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के स्थानांतरण के लिए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने नियम 27 के उपनियम (1) के तहत पूर्व सहमति के लिए कभी आवेदन नहीं किया था।

33. उन्होंने अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता चाहता है कि उसके मामले पर नियम 27 के तहत विचार किया जाए, तो उसके लिए नियम 27 के उपनियम (1) और (2) में उल्लिखित राशि जमा करना आवश्यक था और चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता था।

34. उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान तथ्यों में शामिल लेन-देन जैसे लेन-देन को कवर करने के लिए नीति बनाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, राज्य ने नीति बनाई है और तदनुसार, ऐसे लेन-देन को मान्यता दी गई है, लेकिन केवल 2017 के नियमों (01.03.2017) के लागू होने के बाद। उन्होंने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि पिछले लेन-देन को मान्य नहीं किया जा सकता है, जब नियमों के नए सेट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

35. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अंततः प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की वैकल्पिक प्रार्थना कि चूंकि चूना पत्थर को एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक प्रमुख खनिज घोषित किया गया है, इसलिए इसे लीजहोल्ड अधिकारों को स्थानांतरित करने या धारा 12 ए (6) के तहत इसके आवेदन पर विचार करने की

अनुमति दी जानी चाहिए, पर भी विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त प्रावधान 1957 के अधिनियम से हटा दिया गया है।

प्रतिवादीगण संख्या 5 के तर्क:

36. श्री सुधीर गुसा, प्रतिवादीगण संख्या 5 (जे.के.सीमेंट लिमिटेड) के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने शुरू में कहा कि पूरा विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.01.2016 के निर्णय के पैरा संख्या 38 के इर्द-गिर्द घूमता है और तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता - गोटेन लाइमस्टोन खनिज उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ न केवल कानूनी प्रश्न को समाप्त कर दिया गया है, बल्कि इस संबंध में याचिकाकर्ता का भाग्य भी तय हो गया है।

37. उन्होंने तर्क दिया कि मूल पट्टेदार गोटेन लाइमस्टोन खनिज उद्योग - साझेदारी फर्म थी, जिसका अस्तित्व समाप्त हो गया है और याचिकाकर्ता, जो उक्त फर्म के एक निजी लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित होने का परिणाम है, वह भी यूटीसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है और इस प्रकार, राज्य की कार्यवाही को चुनौती देने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है, खासकर तब, जब पट्टा स्वयं समाप्त हो गया है।

38. यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि खनन पट्टे को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.12.2014 के आदेश द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आदेश को बहाल कर दिया गया था, और इसलिए, याचिकाकर्ता, जो मौजूदा खनन पट्टाधारक नहीं है, 2017 के नियमों के नियम 27 के अनुसार खनन पट्टे के हस्तांतरण का दावा नहीं कर सकता है।

39. उन्होंने तर्क दिया कि 2017 के नियमों का उप-नियम (7) एक स्वतंत्र प्रावधान नहीं है और तर्क दिया कि इसे नियम 27 के शेष भाग और प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता अपने खनन पट्टे को स्थानांतरित करवा सकता है, तब भी, लागू शुल्क के भुगतान के बाद हस्तांतरण के लिए एक औपचारिक आवेदन इस तथ्य को स्थापित करने के अधीन आवश्यक है कि उसके पास मौजूदा और मौजूदा पट्टा अधिकार हैं।

40. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता के दिनांक 10.05.2017 के आवेदन को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28.11.2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया

गया था, जबकि याचिकाकर्ता ने 20 महीने की अत्यधिक देरी के बाद 13.08.2019 को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और तर्क दिया है कि ऐसे मामलों में देरी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

41. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता कंपनी के तत्कालीन निदेशकों के आचरण पर विभिन्न प्रस्तुतियाँ दीं और प्रस्तुत किया कि उन्होंने 08.08.2023 को एक उपक्रम दायर किया था, जबकि गोटन खनिज प्राइवेट लिमिटेड के शेयर पहले ही स्थानांतरित हो चुके थे और गोटन लाइमस्टोन खनिज उद्योग प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन निदेशकों ने भी 23.07.2012 को इस्तीफा दे दिया था।

42. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा 38 में दिए गए निर्देशों को निर्णय के पैरा 32 में कही गई बातों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए तथा तर्क दिया कि उक्त पैरा में की गई टिप्पणियों के अनुसार, राज्य को लोगों के सर्वोत्तम हित में खनिज अधिकारों के हस्तांतरण को विनियमित करना चाहिए।

43. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कि पट्टेदार को याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई चाल को अपनाकर ऐसे अधिकारों का व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा अपनाए गए लेन-देन या कार्यप्रणाली को सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत के विपरीत माना गया है, इसलिए अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा मांगे गए खनन अधिकारों के हस्तांतरण के लिए आवेदन को खारिज किया जाना चाहिए और इसलिए, सही ढंग से खारिज किया जाना चाहिए।

44. श्री गुप्ता ने अभिषेक कुमार सिंह बनाम जी. पटनायक एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जो 2021 (7) एससीसी 613 (पैरा संख्या 58) में रिपोर्ट किया गया और प्रस्तुत किया कि यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की व्याख्या और स्पष्ट नहीं कर सकता है और उच्च न्यायालय केवल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर सकता है जो उस पर बाध्यकारी है।

45. उन्होंने प्रस्तुत किया कि 12.01.2015 से चूना पत्थर को मुख्य खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तर्क दिया कि विचाराधीन खनिज अधिकार केवल नीलामी

के माध्यम से दिए जा सकते हैं जैसा कि 1957 के अधिनियम की धारा 10बी(4) के तहत प्रावधान किया गया है।

46. उन्होंने प्रस्तुत किया कि खनन पट्टे की बहाली और हस्तांतरण के लिए अभ्यावेदन (अनुबंध 23) यूटीसीएल द्वारा दायर किए गए थे, जिसका हस्तांतरण का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उक्त कंपनी (यूटीसीएल) कभी भी खनन पट्टाधारक नहीं थी। उन्होंने गोरे लाल दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य 1976 (2) एससीसी 911 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि राज्य के लिए उचित तरीका आवेदनों को मुख्य खनिज के रूप में और साथ ही गौण खनिज के रूप में भी मानना था।

47. उन्होंने तर्क दिया कि उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 को पढ़कर पट्टा या खनिज अधिकार को मुख्य खनिज के रूप में दिया जाना आवश्यक था और दोहराया कि चूंकि चूना पत्थर एक मुख्य खनिज है, इसलिए 2017 के नियम लागू नहीं होते। उन्होंने इस तर्क के साथ निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के पास हस्तक्षेप करने लायक कोई मामला नहीं है, क्योंकि 2017 के नियम लागू नहीं होते।

प्रतिक्रिया-प्रस्तुतियाँ:

48. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शर्मा ने प्रतिक्रिया में अपनी दलीलें वहीं से शुरू कीं, जहाँ श्री गुप्ता ने छोड़ी थीं।

49. उन्होंने तर्क दिया कि श्री गुप्ता का यह तर्क कि 2017 के नियम गौण खनिज के लिए लागू नहीं होते, पूरी तरह से गलत है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन खनन पट्टा गौण खनिज के रूप में दिया गया था।

50. उन्होंने कहा कि नियम 27 का उपनियम (7) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा संख्या 38 में दिए गए निर्देशों का परिणाम है और यदि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया भी जाए तो याचिकाकर्ता ने 10.05.2017 को जो आवेदन दाखिल किया था, वह प्रमुख सचिव को संबोधित था, जबकि नियम 27 के अनुसार खनन अभियंता के समक्ष आवेदन दाखिल किया जाना आवश्यक है।

51. उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे आवेदन की तिथि पर याचिकाकर्ता पट्टाधारक नहीं था और इसलिए वह तथाकथित हस्तांतरण के अधिकार को बनाए या लागू नहीं कर सकता था।

52. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में यह भी तर्क दिया कि निर्णय अवमाननापूर्ण था और केवल याचिकाकर्ता के लिए नहीं था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि उपनियम (7) द्वारा कवर किए गए हस्तांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है, जैसा कि उपनियम (1) में हस्तांतरण के लिए लागू है, इसलिए याचिकाकर्ता ने आवेदन दाखिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि आवेदन दाखिल करने की कोई औपचारिकता आवश्यक थी, तो प्रतिवादीगण-राज्य को इसके लिए कहना चाहिए था। यदि याचिकाकर्ता को कोई औपचारिक आवेदन दाखिल करने के लिए कहा गया होता, तो वह ऐसा ही करता।

53. उन्होंने कहा कि यदि अलग-अलग लेन-देन को अलग-अलग देखा जाए, तो वह अवैध नहीं है। उन्होंने कहा कि संचयी रूप से देखे गए लेन-देन को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध माना है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के साथ केवल इसलिए प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लेन-देन को एक युक्ति माना है।

54. उन्होंने तर्क दिया कि श्री गुसा का यह तर्क कि विषयगत खनन पट्टा केवल एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10 बी(4) और (7) के अनुसार नीलामी के माध्यम से दिया जा सकता है, गलत है। उन्होंने कहा कि पट्टा 1986 के नियमों के तहत एक लघु खनिज के रूप में दिया गया था और यहां तक कि हस्तांतरण के लिए आवेदन भी ऐसे नियमों के तहत दायर किया गया था।

55. उन्होंने जोर देकर कहा कि चूना पत्थर को हमेशा इसके उपयोग के आधार पर प्रमुख खनिज के साथ-साथ गौण खनिज दोनों के रूप में माना गया है जैसा कि रुक्मणी बाई बनाम राज्य मध्य प्रदेश, (1975) 1 एससीसी 627 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है और तर्क दिया कि प्रतिवादीगण संख्या 5 के मुंह से ऐसा विवाद उठाना उचित नहीं है, जब प्रतिवादीगण संख्या 5 को खनन पट्टे के आंशिक हस्तांतरण के लिए आवेदन 1986 के नियमों के तहत प्रस्तुत किया गया था।

56. 2022 एससीसी ऑनलाइन 1119 (सेबी बनाम राज कुमार नागपाल) पैरा संख्या 99- 104 में रिपोर्ट किए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि 2017 के नियम पूर्वव्यापी हैं और याचिकाकर्ता के मामले में भी वही लागू होते हैं, विशेष रूप से, क्योंकि नियम 27 के उप-नियम (7) से (11) याचिकाकर्ता के

मामले में फैसले के पैरा संख्या 38 में किए गए अवलोकन के अनुसरण में पेश किए गए थे।

57. पक्षों के विद्वान वकील को सुना।

चर्चा और निष्कर्ष:

58. इस मामले की उत्पत्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 20.01.2016 के निर्णय के पैरा संख्या 38 में निहित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा दायर एक अपील में पारित किया गया था। अपील को स्वीकार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:-

"38. तदनुसार, इस अपील को स्वीकार किया जाता है और उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द किया जाता है। तथापि, हम राजस्थान राज्य को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक महीने के भीतर मामले में अपनी नीति तैयार करने और अधिसूचित करने का निर्देश देते हैं। राजस्थान राज्य इसके बाद एक महीने के भीतर इस प्रकार तैयार की गई नीति के आलोक में प्रश्नगत खनन पट्टे के संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है। ऐसा निर्णय लिए जाने तक, यथास्थिति बनाए रखी जा सकती है।"

59. यह ध्यान देने योग्य है कि साझेदारी फर्म को निजी लिमिटेड कंपनी में बदलने के लेन-देन को याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुकदमे के पहले के दौर (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9669/2014) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा हस्तांतरण नहीं माना गया था और इस दृष्टिकोण की पुष्टि डिवीजन बेंच द्वारा की गई थी। यह एक तथ्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 20.01.2016 के निर्णय के माध्यम से माना है कि सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, शेयरों की बिक्री अपने आप में परिसंपत्तियों की बिक्री नहीं है, लेकिन यह सिद्धांत कानून की नीति को प्रभावी करने के लिए जहां भी आवश्यक हो, कॉर्पोरेट घूँघट को भेदने के सिद्धांत के अधीन है।

60. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे बढ़कर माना कि वर्तमान मामले में, कॉर्पोरेट घूँघट को भेदने का सिद्धांत लागू होता है। इसलिए शेयरों के हस्तांतरण को वैधानिक रूप से आवश्यक सक्षम प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना, विचार के लिए खनन पट्टे की बिक्री के वास्तविक लेनदेन को कवर करने के लिए एक आवरण के रूप में माना गया था।

61. इसलिए, जहां तक साझेदारी फर्म को कंपनी में बदलने तथा निजी लिमिटेड कंपनी के शेयर को यूटीसीएल को हस्तांतरित करने का मुद्दा है, माननीय सर्वोच्च

न्यायालय ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया है। इस लेनदेन को हस्तांतरण के प्रावधान और प्रक्रिया को दरकिनार करने का एक उपकरण मानते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में एक नीति बनाने तथा संबंधित खनन पट्टे के संबंध में उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

62. प्रतिवादीगण संख्या 5 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुप्ता का तर्क यह रहा है कि - माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को "संबंधित खनन पट्टे" के संबंध में आदेश पारित करने का निर्देश दिया है, न कि याचिकाकर्ता को, और इसलिए, याचिकाकर्ता को कोई रियायत दिए जाने की आवश्यकता नहीं है, यह तर्कहीन और अस्वीकार्य है।

63. क्योंकि, यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इरादा केवल खनन पट्टे के संबंध में उचित आदेश पारित करना था, जिसमें याचिकाकर्ता के अधिकारों को छोड़ना या अनदेखा करना था, तो आदेश के पैरा संख्या 38 में जो संकेत दिया गया है, उसे निर्देशित करने का कोई अवसर नहीं था। ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करना और खनन पट्टे को रद्द करने वाले दिनांक 16.12.2014 के आदेश को बहाल करना ही पर्याप्त होता। परिणाम स्वाभाविक रूप से सामने आते और राज्य कानून के अनुसार खनन पट्टे की नीलामी करने के लिए स्वतंत्र होता।

64. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई शर्त से यह दृष्टिकोण और भी पुष्ट होता है - इसने राज्य को उस समय तक 'यथास्थिति' बनाए रखने का निर्देश दिया था। इस न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, जैसा कि प्रार्थना की गई थी - नीति तैयार करने के बाद, राज्य को इस तरह से तैयार की गई नीति के आलोक में याचिकाकर्ता के अधिकारों पर निर्णय लेना आवश्यक था।

65. प्रतिवादीगण संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री गुप्ता ने अभिषेक कुमार सिंह (सुप्रा) के मामले में निर्णय, विशेष रूप से उक्त निर्णय के पैरा-58 का हवाला दिया, जो इस न्यायालय की राय में वर्तमान मामले में शामिल मुद्दे के सार पर कोई प्रकाश नहीं डालता है।

66. उपर्युक्त निर्णय का पैरा 58 नीचे पुनः उद्धृत है:-

"58. सबसे पहले, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका की स्थिरता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति का उत्तर देना उचित समझते हैं। हमें एक से अधिक कारणों से इस प्रारंभिक आपत्ति को अस्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यह अच्छी तरह से

स्थापित स्थिति है कि यदि समाप्ति आदेश को संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत प्राकृतिक न्याय या मौलिक अधिकारों के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जाती है, तो इस तरह की शिकायत संवैधानिक न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका के माध्यम से लाई जा सकती है। यह अलग बात है कि यह न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत सीधे शिकायत पर विचार करने में अनिच्छुक हो सकता है और इसके बजाय याचिकाकर्ता(ओं) को पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उपाय का उपयोग करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष भेज सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस न्यायालय को तब प्रासंगिक पहलुओं पर उच्च न्यायालय के फैसले का लाभ मिलेगा। दूसरे शब्दों में, यह रिट याचिका की स्थिरता का सवाल नहीं है, बल्कि ऐसे मामलों में अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका पर विचार करने में सावधानी के साथ विवेक का प्रयोग करने का सवाल है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, अवमानना याचिकाओं और स्थानांतरण याचिका के रूप में अन्य कार्यवाही लंबित हैं, जिसमें 2-3-2020 का समाप्ति आदेश विषय-वस्तु है। इस प्रकार, इन मामलों में तर्क ओवरलैपिंग होंगे। उसमें, इस न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में भी इसी आदेश को चुनौती दी गई है। तथ्य यह है कि इसी तरह के अन्य प्रभावित व्यक्तियों ने सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की हैं और जिन्हें लंबित बताया गया है, इस न्यायालय के लिए रिट याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने में कोई बाधा नहीं हो सकती है। क्योंकि, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आशय के मुद्दे का उत्तर केवल इस न्यायालय द्वारा अवमानना याचिकाओं में उचित रूप से दिया जाना चाहिए। पक्षों के बीच पिछली कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की व्याख्या या व्याख्या करना उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं है। उच्च न्यायालय केवल इस न्यायालय के आदेश का पालन कर सकता है जो उसके लिए बाध्यकारी है। तदनुसार, हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका की स्थिरता के बारे में प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए प्रारंभिक आपत्ति से प्रभावित नहीं हैं, जो कि इसी तरह के व्यक्तियों द्वारा सीधे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के लिए दायर की गई है। दिनांक 2-3-2020 के आदेश के अनुसार, जो अवमानना याचिकाओं के दूसरे सेट का भी विषय है।

67. गोरेलाल दुबे (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जहां दो आवेदक हैं - एक ने लघु खनिज के रूप में चूना पत्थर के लिए पट्टा मांगा, जबकि दूसरे ने इसे प्रमुख खनिज के रूप में आवेदन किया, कार्रवाई का उचित तरीका राज्य सरकार को दोनों आवेदनों की समीक्षा करने, यह आकलन करने का निर्देश देना है कि क्या क्षेत्र में चूना पत्थर की गुणवत्ता इसे लघु खनिज के रूप में उत्खनन के लिए या

इसे प्रमुख खनिज के रूप में खनन करने के लिए पट्टा देने की गारंटी देती है, और फिर तदनुसार पट्टा देने की कार्यवाही करें।

68. अब जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या 2017 के नए शामिल नियम, विशेष रूप से, नियम 27 के उप-नियम (7) और (8), याचिकाकर्ता के कारण को कवर करते हैं और उनकी सेवा करते हैं?

69. ऐसे उद्देश्य के लिए, 2017 के नियम 27 के रूप में राज्य द्वारा तैयार की गई योजना को ध्यान में रखना आवश्यक है। जहां तक इस न्यायालय के समक्ष विवाद का संबंध है, यह नियम 27 के उप-नियम (7) और (8) के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

27(7):- निम्नलिखित मामलों को भी हस्तांतरण माना जाएगा,

(i) एक प्रकार के व्यवसाय संगठन से दूसरे प्रकार के व्यवसाय संगठन में परिवर्तन, जैसे भागीदारी, सीमित दायित्व भागीदारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या किसी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसाय गतिविधियों का कोई भी रूप, व्यवसाय संगठन के दूसरे रूप में;

(ii) भागीदारी फर्म के भागीदार में परिवर्तन;

(iii) किसी कंपनी में शेयरों का हस्तांतरण, जिसके परिणामस्वरूप उक्त कंपनी के प्रबंधन या स्वामित्व अधिकार के नियंत्रण में परिवर्तन होता है;

(iv) पट्टेदार या लाइसेंसी की कंपनी का किसी अन्य कंपनी में विलय या समामेलन; और

(v) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लिमिटेड कंपनी में परिवर्तन:

27(8):- पट्टेदार या लाइसेंसी उपनियम (7) में उल्लिखित किसी भी परिवर्तन के बारे में उपनियम (9) के अनुसार आवेदन शुल्क और प्रीमियम राशि के साथ साठ दिनों के भीतर संबंधित खनन अभियंता या सहायक खनन अभियंता को सूचित करेगा। ऐसे मामले में, स्थानांतरण, प्रासंगिक कानून के अंतर्गत, साझेदार या निदेशक के परिवर्तन की तारीख से प्रभावी होगा।

70. पूर्ववर्ती नियम 1986 के नियम 15 को नियम 2017 के नियम 27 के साथ पढ़ने पर पता चलता है कि उप-नियम (6) तक प्रावधान कमोबेश राजस्थान लघु खनिज रियायत नियम 1986 के नियम 15 के समरूप हैं। चूंकि 1986 के नियमों में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए लेन-देन को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लेन-देन की गहन जांच करने के बाद यह माना कि विचाराधीन लेन-देन वास्तव में पट्टा-अधिकारों की बिक्री या हस्तांतरण था।

71. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अवलोकन किया गया था, उसे अब नियम 2017 के नियम 27 के उप-नियम (7) के रूप में विशेष रूप से प्रदान किया गया है और खंड (i) से (v) में सूचीबद्ध लेन-देन के संबंध में एक डीमिंग-फिक्शन प्रदान किया गया है और ऐसे परिवर्तनों को हस्तांतरण माना गया है।

72. तदनुसार, साझेदारी फर्म का निजी लिमिटेड कंपनी में रूपांतरण, तथा निजी लिमिटेड कंपनी के शेयरों का सीमित कंपनी में हस्तांतरण भी नियम 27 के उप-नियम (7) के खंड (i) और (iii) में निहित प्रावधानों के आधार पर हस्तांतरण माना गया है।

73. नियम 27 के उप-नियम (1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व सहमति के बिना पट्टा या लाइसेंस को सौंपा, उप-पट्टे पर दिया, बंधक रखा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। उप-नियम (2) से उप-नियम (6) तक के प्रावधान हस्तांतरण की प्रणाली प्रदान करते हैं, जिसके बाद उप-नियम (7) आकस्मिकताओं को समाहित करता है या खंड (i) से (v) में उल्लिखित परिवर्तनों को भी हस्तांतरण माना जाएगा।

74. इस आशय के व्यापक निवेदन किए गए हैं कि आक्षेपित आदेश अवैध और विपरीत है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है और इसलिए भी कि आक्षेपित आदेश में कारण नहीं दिए गए हैं। यदि उपनियम (8) में निहित प्रावधानों को, जो फर्म के संविधान में परिवर्तन करने या उसे प्रभावित करने की प्रक्रिया है, पर विचार किया जाए, तो निर्विवाद रूप से, इसमें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस न्यायालय के अनुसार, विशिष्ट प्रावधान के अभाव में भी, यदि नागरिकों या पट्टेदारों के लिए मौलिक अधिकारों का न्यायनिर्णयन किया जा रहा है, तो संबंधित प्राधिकारी को सुनवाई के अधिकार का सम्मान करना चाहिए, जिसे प्राकृतिक न्याय की नींव का आधार माना गया है।

75. नियम 27 का उपनियम (8) एक मशीनरी प्रावधान है; यह तब लागू होता है जब फर्म के संविधान या उसके स्वामित्व में परिवर्तन करने या उसमें परिवर्तन करने से पहले पूर्व सहमति प्राप्त कर ली गई हो, जैसा कि उपनियम (7) के खंड (i) से (v) में उल्लेख किया गया है।

76. वास्तव में, सहमति देना या अस्वीकार करना एक मौलिक अधिकार है, जिसके लिए अनुमति देने से इनकार करने पर कारणों को दर्ज करना आवश्यक है। एक बार अनुमति दे दी गई है तो जो किया जाना आवश्यक है वह एक मंत्रिस्तरीय कार्य है।

इसलिए, यदि सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, तो वर्तमान मामले के संबंध में आदेश में कोई त्रुटि नहीं की जा सकती है। वर्तमान मामले में, जैसा कि तथ्यों को स्वीकार किया गया था, भले ही याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया हो, इससे शायद ही कोई फर्क पड़ता।

77. इस न्यायालय को श्री शर्मा के इस तर्क में भी कोई सार नहीं मिला कि आदेश एक तर्कपूर्ण आदेश नहीं है। दिनांक 28.11.2017 के आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने से पता चलता है कि राज्य सरकार ने माना है कि किसी कंपनी के निदेशक का परिवर्तन हस्तांतरण के दायरे में आता है और कंपनी ने इस तरह के हस्तांतरण को प्रभावित करने के लिए पूर्व सहमति प्राप्त नहीं की थी। राज्य सरकार ने आगे माना है कि याचिकाकर्ता को दी गई लीज डीड का निर्धारण 16.12.2014 को किया गया था और इसलिए खनन पट्टे को यूटीसीएल के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

78. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 16.12.2014 के आदेश के द्वारा, साझेदारी फर्म गोटेन लाइमस्टोन खनिज उद्योग के नाम पर खनन पट्टा समाप्त/रद्द कर दिया गया था, जबकि विषयगत लेनदेन को हस्तांतरण माना गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समन्वय पीठ के दिनांक 25.03.2015 के निर्णय को अपास्त किया है और साथ ही इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 14.05.2015 के निर्णय को भी अपास्त किया है। और परिणामस्वरूप, दिनांक 16.12.2014 का आदेश पुनर्जीवित हो गया, जिसके द्वारा साझेदारी फर्म - गोटेन लाइमस्टोन खनिज उद्योग के पक्ष में खनन पट्टा रद्द कर दिया गया था।

79. ऐसा करते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा संख्या 38 में इस मुद्दे को जीवित रखा है और राज्य सरकार को अपनी नीति तैयार करने और अधिसूचित करने और प्रश्नगत खनन पट्टे के संबंध में एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। इस न्यायालय का विचार है कि राज्य का यह रुख कि चूंकि खनन पट्टा निर्धारित हो चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता के हस्तांतरण के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप नहीं है। और भी अधिक, जब राज्य को प्रश्नगत खनन पट्टे के भाग्य पर विचार करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किया गया था।

80. लेकिन फिर, इस न्यायालय के विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादीगण राज्य याचिकाकर्ता की होल्डिंग कंपनी - अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टा हस्तांतरित करने के लिए बाध्य था?

81. राज्य ने याचिकाकर्ता के आवेदन को अनिवार्य रूप से खारिज कर दिया है, जबकि विषयगत लेनदेन को हस्तांतरण माना है और पाया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रश्नगत खनन पट्टा निर्धारित हो चुका है, कोई पूर्व सहमति प्राप्त नहीं की गई थी।

82. इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि 2017 के नियमों के लागू होने के बाद विषयगत लेनदेन एक हस्तांतरण था। अपील को स्वीकार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को इस संबंध में एक नीति बनाने का निर्देश दिया था। और इसलिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के हस्तांतरणों से किस तरह निपटा जाए।

83. नियम 27 के उप-नियम (8) में यह प्रावधान है कि जब परिवर्तन या लेन-देन, जिसे काल्पनिक मानकर बिक्री माना जाता है, को प्रभावी किया जाना आवश्यक है, तो पट्टेदार या लाइसेंसधारी का यह दायित्व होगा कि वह संबंधित खनन इंजीनियर या सहायक इंजीनियर को उप-नियम (9) के अनुसार लागू आवेदन शुल्क और प्रीमियम राशि के साथ 60 दिनों के भीतर परिवर्तनों के बारे में सूचित करे।

84. इस न्यायालय के अनुसार, 2017 के नियम न तो पिछले लेन-देन को अपने दायरे में लाते हैं और न ही वे उन लेन-देनों के सत्यापन का प्रावधान करते हैं जो उक्त नियमों के प्रख्यापन से पहले हुए हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता नियम 27 के उप-नियम (8) या उप-नियम (9) में जो प्रावधान किया गया है, उसका लाभ नहीं उठा सकता।

85. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए लेन-देन या उसके द्वारा किए गए परिवर्तन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही हस्तांतरण माना जा चुका है। नियम 27 में शायद ही ऐसा कुछ है जो पिछले परिवर्तनों या पिछले लेन-देन को कवर करता हो। इसलिए, याचिकाकर्ता 2017 के नियमों की नई बनाई गई नीति या नियम 27 का लाभ नहीं उठा सकता।

86. इस न्यायालय के अनुसार, उप-नियम (7) याचिकाकर्ता के मामले को कवर करने वाला सकारात्मक प्रावधान नहीं है - बल्कि यह एक काल्पनिक कल्पना है जो यह प्रावधान करती है कि उप-नियम (7) के खंड (i) से (v) में सूचीबद्ध परिवर्तन या लेन-देन को हस्तांतरण माना जाएगा।

87. इस न्यायालय के अनुसार, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि 2017 के नियमों के नए शामिल नियम 27 के आधार पर, उप-नियम (7) के तहत कवर किए गए मामलों के लिए पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है, बिल्कुल अस्वीकार्य है।

88. उप-नियम (7) में यह प्रावधान है कि पट्टेदार की संरचना या गठन में प्रत्येक परिवर्तन हस्तांतरण के बराबर होगा। उप-नियम (7) वास्तव में, लेन-देन के दायरे का विस्तार करता है, जो हस्तांतरण के बराबर है। याचिकाकर्ता ने जो लेन-देन किए हैं, उनकी प्रकृति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही हस्तांतरण माना जा चुका है। और, उप-नियम (7) नियमों में एक विशिष्ट प्रावधान के अलावा और कुछ नहीं है, ताकि किसी भी प्रकार के भ्रम को दूर किया जा सके।

89. दूसरे शब्दों में, उप-नियम (7) एक स्वतंत्र प्रावधान नहीं है और यह नियम 27 में निहित मूल प्रावधान का अभिन्न अंग है। नियम 27 एक अधिदेश के साथ शुरू होता है कि पट्टेदार या लाइसेंसधारी सक्षम प्राधिकारी की लिखित में पूर्व सहमति के बिना पट्टे को तीसरे पक्ष को सौंपना, उप-पट्टा देना, बंधक बनाना या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित नहीं करेगा और उप-नियम (7) नियम 27 का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उप-नियम (7) को उप-नियम (1) से अलग और स्वतंत्र रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उपनियम (1) में दिए गए लिखित में पूर्व सहमति आवश्यक नहीं होगी।

90. यदि याचिकाकर्ता का पक्ष स्वीकार कर लिया जाता है, तो एक विषम स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। खनन पट्टे के स्पष्ट हस्तांतरण के मामले में, पट्टेदार को पूर्व अनुमति लेनी होगी, जबकि दिखावटी या भ्रामक हस्तांतरण के मामले में, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रयास किया गया है, कोई सहमति आवश्यक नहीं होगी। यदि ऐसी व्याख्या की जाती है, तो नियम 27 के प्रावधान को विफल कर देगी और जनता के विश्वास को हिला देगी, साथ ही इस अवधारणा को भी खारिज कर देगी कि खनिज अधिकार राज्य के अधिकार क्षेत्र में हैं और उन्हें सार्वजनिक हित में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

91. यह ध्यान देने योग्य है कि आमतौर पर हस्तांतरण बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख के माध्यम से किए जाते हैं, जबकि उप-नियम (7) के खंड (i) से (v) में दिए गए अनुसार फर्म के संविधान में परिवर्तन प्रासंगिक कानूनों अर्थात् भागीदारी अधिनियम

या कंपनी अधिनियम या अन्य अधिनियमों के तहत अपनाई गई प्रक्रिया के आधार पर होता है, जिसके तहत पट्टेदार का संविधान शासित होता है।

92. भागीदारी फर्म के कंपनी में परिवर्तन और/या दो कंपनियों के विलय या समामेलन के मामले में, परिवर्तन कानून के संचालन द्वारा होता है और हस्तांतरण/बिक्री आदि के मामलों के विपरीत, कोई अलग दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है: उप-नियम (8) को दिए गए तरीके से डाला गया है। यह पट्टेदार या लाइसेंसधारी को संबंधित खनन इंजीनियर या सहायक खनन इंजीनियर को ऐसे परिवर्तन के 60 दिनों की अवधि के भीतर सूचित करने का निर्देश देता है। और ऐसी विधिक स्थिति के कारण ही उपनियम (8) में यह प्रावधान है कि हस्तांतरण, भागीदार या निदेशक के ऐसे परिवर्तन की तिथि से प्रभावी होगा, जैसा भी मामला हो, प्रासंगिक कानून के अंतर्गत।

93. दूसरे शब्दों में, चूंकि पूर्व सहमति प्राप्त होने के पश्चात् पट्टेदार के संविधान में परिवर्तन विधि के संचालन द्वारा होता है, इसलिए पट्टेदार पर यह दायित्व डाला गया है कि वह 60 दिनों की अवधि के भीतर खनन अभियंता को सूचित करे और चूंकि सूचना देने का कार्य केवल प्रक्रियात्मक कार्य है, इसलिए नियम 28 के खंड (xix) में यह प्रावधान है कि यदि पट्टेदार निर्दिष्ट समय के भीतर उपर्युक्त परिवर्तन की सूचना देने में विफल रहता है, तो ऐसा 500/- रुपये प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क के भुगतान पर किया जाएगा, जो अधिकतम 2,00,000/- रुपये तक होगा।

94. लेकिन खंड (xix) में इस तरह की शर्त का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि 60 दिनों की समाप्ति के बाद विलंब शुल्क के भुगतान के साथ मात्र सूचना देना ही पर्याप्त होगा, ताकि राज्य सरकार से किसी पूर्व अनुमति के बिना हस्तांतरण का दावा किया जा सके।

95. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में **सेबी** (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया कि 2017 के नियम पूर्वव्यापी रूप से लागू होते हैं। यह न्यायालय याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है कि 2017 के नियम पूर्वव्यापी प्रकृति के हैं और पहले से हो चुके लेन-देन पर लागू होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दो शब्दों "रेट्रोस्पेक्टिव" और "रेट्रोएक्टिव" के बीच अंतर किया है। किसी भी कानून की पूर्वव्यापी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वह किसी ऐसे कार्य या लेन-देन से संबंधित हो जो अभी भी चल रहा हो, पूरा नहीं हुआ हो और पूरा होने की प्रक्रिया में हो। सिर्फ इसलिए कि कोई कानून कुछ परिस्थितियों पर काम करता है जो

उसके पारित होने से पहले की हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह पूर्वव्यापी है यदि उस लेन-देन के कुछ चरण शेष हैं।

96. हो सकता है कि नियम 27 के उप-नियम (7) और (8) को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार शामिल किया गया हो, लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है कि नियम पहले से संपन्न लेनदेन पर लागू होंगे।

97. यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि 2017 के नियम 01.03.2017 से प्रभावी हो गए हैं। यह कानून की स्थापित पूर्वधारणा है कि किसी भी अधिनियम या नियम की भावी प्रयोज्यता होगी, जब तक कि विशिष्ट अभिव्यक्ति या इरादे से, उन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव देने का इरादा न हो।

98. इस न्यायालय को 2017 के नियमों, विशेषकर नियम 27(8) में शायद ही कोई ऐसी बात मिले, जो यह सुझाव दे कि इसकी पूर्वव्यापी प्रयोज्यता होगी या यह संपन्न लेनदेन या पहले से हो चुके लेनदेन पर लागू होगी।

99. वस्तुतः, उप-नियम (8) पट्टेदार या लाइसेंसधारी को नियम 27 के उप-नियम (7) में उल्लिखित किसी भी परिवर्तन के बारे में खनन अभियंता को सूचित करने का निर्देश देता है। यदि नियम के निर्माता ऐसा चाहते, तो वे विशेष रूप से यह प्रावधान कर सकते थे कि लेनदेन करने वाले पट्टेदार या लाइसेंसधारी को निर्धारित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित करना आवश्यक होगा।

100. चूंकि नियम 27 के उपनियम (7) और (8) में इस प्रकार की कोई बात नहीं दी गई है, इसलिए इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि नियम 27(7) 01.03.2017 से ही लागू होगा और याचिकाकर्ता के लेनदेन सहित पूर्ववर्ती लेन-देन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के मामले में दिनांक 20.01.2016 के निर्णय (2016 (4) एससीसी 469) में निर्धारित कानून के अंतर्गत आएंगे।

101. इस न्यायालय के अनुसार, यदि कोई पट्टेदार या लाइसेंसधारी संविधान में परिवर्तन लाने का प्रस्ताव करता है, तो उसे ऐसे परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। चूंकि उपनियम (7) द्वारा कवर किए गए परिवर्तनों के मामले में कोई अंतर-दस्तावेज निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए केवल एक सूचना अनिवार्य है और यह पर्याप्त होगी, जबकि बिक्री या असाइनमेंट आदि के माध्यम से खनिज अधिकारों के हस्तांतरण के मामले में, फॉर्म नंबर 12 में एक अलग हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।

102. ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि नियम 27 के उप-नियम (1) या उप-नियम (7) के अंतर्गत आने वाले प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष हस्तांतरण के मामले में, सक्षम प्राधिकारी की लिखित में पूर्व सहमति अनिवार्य है।

103. राज्य सरकार की पूर्व सहमति लेने के बाद किए गए ऐसे हस्तांतरण के मामले में, पट्टेदार या लाइसेंसधारी को 60 दिनों की अवधि के भीतर खनन अभियंता को परिवर्तन के बारे में सूचित करना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता उप-नियम (8) के आधार पर अपने अधिकारों का दावा करना चाहता था, तो उसे नियमों के लागू होने के 60 दिनों के भीतर संबंधित खनन अभियंता को सूचित करना चाहिए था, भले ही उसका यह विचार हो कि पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है।

104. निर्विवाद रूप से, 2017 के नियम 01.03.2017 को लागू हुए और याचिकाकर्ता ने सबसे पहले 10.05.2017 को प्रतिनिधित्व के माध्यम से राज्य सरकार को आवेदन दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसा पत्र राज्य सरकार को संबोधित किया गया था, न कि संबंधित खनन अभियंता को। इस तथ्य के अलावा कि अभ्यावेदन 60 दिनों की समाप्ति के बाद किया गया है, इसे गलत प्राधिकारी को संबोधित किया गया है।

105. इसके अलावा, उप-नियम (8) पर एक नज़र डालने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पट्टेदार उप-नियम (7) में उल्लिखित परिवर्तनों के बारे में आवेदन और उप-नियम (9) के अनुसार लागू शुल्क और प्रीमियम राशि के साथ सूचित करेगा। याचिकाकर्ता ने न तो आवेदन शुल्क जमा किया था और न ही उसने उप-नियम (9) के अनुसार प्रीमियम राशि जमा की थी। ऐसी स्थिति में, भले ही यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता के मामले को 2017 के नियम 27 के उप-नियम (7) और उप-नियम (8) द्वारा शासित किया जाना आवश्यक था, क्योंकि याचिकाकर्ता उप-नियम (8) के आदेश का पालन करने में विफल रहा है, (एक अभिव्यक्ति "करेगा" का उपयोग किया गया है), यह न्यायालय स्पष्ट रूप से मानता है कि याचिकाकर्ता का आवेदन अक्षम था।

106. चूंकि याचिकाकर्ता वैधानिक आवश्यकता का पालन करने में विफल रहा है, इसलिए गोटेन लाइमस्टोन खनिज उद्योग के नाम पर मौजूद खनन पट्टे को गोटेन लाइमस्टोन खनिज उद्योग प्राइवेट लिमिटेड और फिर अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, जैसा कि प्रार्थना की गई है।

107. यह न्यायालय आगे यह जोड़ना चाहेगा कि खनिज अधिकार राज्य सरकार के मूल्यवान संसाधन हैं। चूंकि वे राज्य के हैं और उन्हें सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत के

अनुसार निपटाया और निपटाया जाना है। यूटीसीएल को खनन अधिकारों को गुप्त रूप से हस्तांतरित करने के याचिकाकर्ता के प्रयास को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नकार दिया गया है। इस तरह के प्रयास को याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना की गई तरीके से मान्य नहीं किया जा सकता है।

108. केवल प्रीमियम की मामूली राशि का भुगतान करके जो उप-नियम (9) के अनुसार दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी और पच्चीस हजार रुपये का नाममात्र आवेदन शुल्क, याचिकाकर्ता अप्रत्यक्ष रूप से वह हासिल नहीं कर सकता है, जो वह सीधे नहीं कर सकता है।

109. उपरोक्त चर्चाओं के परिणामस्वरूप यह न्यायालय राज्य सरकार द्वारा पारित दिनांक 28.11.2017 के निर्णय की पुष्टि करता है।

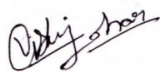
110. अतः रिट याचिका विफल हो जाती है।

111. सभी लंबित अंतरिम आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(दिनेश मेहता), न्यायाधीश

अरविंद-अरुण वी/-

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़